

श्री सरजू पाण्डेय : बहुत से भारतीय जो विदेशों में हैं उनकी पूंजी वहां की सरकारें जब्त कर लेती हैं और उन लोगों को हिन्दुस्तान भेज देती हैं और यहां हिन्दुस्तान की सरकार ऐसी शर्तें लगाती है कि वह हिन्दुस्तान में रोजगार नहीं कर सकते तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा कदम भीष्ट उठायेगी ताकि वह भारतीय जो विदेशों में हैं वह यहां भारत में अपनी पूंजी आसानी से लगा कर रोजगार, धंधा कर सकें ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा मैंने कहा हम पहले स्वामित्व और सामझेदारी करने वाली कम्पनियों में, व्यापार और कारोबार करने वाली कम्पनियों में पूंजी लगाने की इजाजत नहीं देते थे लेकिन जब उन्होंने हमसे कहा कि इसमें भी हमें इजाजत दीजिये तो हमने इसमें भी इजाजत दे दी है। महज इस चीज की सुरक्षा रक्खी है कि जो पूंजी वह यहां लायें या जो उन्हें यहां मुनाफ़ा हो उसे वह वापिस विदेश में न ले जाएं। इसके अलावा और कोई ऐसी शर्तें हमने उन पर नहीं लगाई हैं जिससे कि उनको कोई दिक्कत महसूस हो।

श्री प्रेमचन्द बर्मा : डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि हम उनसे यह नहीं पूछेंगे कि वह पैसा कहां से लाये हैं और मैं मानता हूं कि यह बहुत अच्छा आश्वासन उन्होंने दिया है। इसके साथ ही मैं उनसे यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वह हाउस को इस बात का भी आश्वासन देने को तैयार हैं कि जो यहां के लोग ब्लैकमार्केट का रुपया उनके जरिए अपने बिज़नेस में लगायेंगे उस बारे में भी कोई पूरी जांच पड़ताल का वह ध्यान रक्खेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : यह आश्वासन मैं नहीं दे सकता।

SHRI D. N. PATODIA : The hon. Minister has said that Government would welcome the foreign money owned by Indians abroad. In spite of this welcome, there is positively something which is hindering these people from coming to India. May I, therefore, know whether this is the

only condition that those foreigners who are of Indian origin will not be permitted to take their money back or whether there are some other conditions also ? In this context, may I also know the specific types of facilities apart from this which were demanded by these investors ?

SHRI MORARJI DESAI : As far as I can understand, the only difficulty is that stands in the way of these people is that they seem to be earning much better in London where they are investing this, and they want that I must assure them that they will earn better than that here, which assurance I am not able to give.

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, आनरेबुल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि वह उनको बैलकम करने को तैयार हैं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह महज बैलकम करने के अलावा क्या कोई स्पेशल कंसिडरेशन भी आप उनके साथ करेंगे ?

आंध्र प्रदेश में आदिवासियों और हरिजनों की दशा

\*316. श्री प्रकाशचोर शास्त्री : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के हरिजनों तथा आदिवासियों की दशा बड़ी दयनीय है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी दशा में सुधार करने के लिये कारगर कार्यवाही करने का है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI MUTHYAL RAO) : (a) No, Sir. Such a general statement is not warranted by the circumstances.

(b) The question of Government taking special steps in this context, therefore, does not arise.

The Government, however, have been taking effective steps for the amelioration of the welfare of Scheduled Castes and

**Scheduled Tribes as envisaged in the Constitution of India. So far, nearly Rs. 14 crores have been utilised from the backward classes sector alone on the welfare of Harijans and Adivasis in Andhra Pradesh.**

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, बैसे तो आम तौर पर सारे भारतवर्ष में हरिजनों और आदिवासियों की दशा शोचनीय है परन्तु आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से शोचनीय है क्योंकि वहां की सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर उनके प्रति अपनी घृणा का परिचय सार्वजनिक रूप में दे देते हैं जैसा कि पीछे आंध्र प्रदेश के एक मिनिस्टर यिम्मा रैड्डी ने किया और उसकी यहां और आंध्र के अन्दर पर्याप्त चर्चा रही थी। अभी उप मंत्री महोदय ने बतलाया कि आंध्र प्रदेश में उन सबकी दशा सुधारने के बास्ते वह कुछ उपाय करने के लिए जा रहे हैं तो क्या मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और उनको इस देश के नागरिक होने के नाते समान अधिकार प्राप्त रहें इसके लिए कौन से आंध्र प्रदेश में आपने उपाय बतें हैं अथवा बताने जा रहे हैं ?

श्री मुख्याल राय : श्रीमन्, इसके पहले यह सवाल सदन में आया था और इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। चर्चा होने के बाद सदन ने क्या फैसला किया इसे आप भी जानते हैं फिर उस सवाल को जो वह उठा कर यह कहते हैं कि किसी मंत्री महोदय की वजह से सारे हरिजनों की हालत खराब है तो मैं यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : शायद मैं अपने प्रश्न को मंत्री महोदय को नहीं समझा पाया। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का यह विभाग आंध्र प्रदेश के सम्बन्ध में क्या विशेष उपाय बतल रहा है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति सरकार के स्तर पर न हो ? यह मेरा प्रश्न था।

श्री मुख्याल राय : सरकार के स्तर पर कोई घटना ऐसी नहीं हुई। शायद मेरे साथी उस तरफ़ इशारा कर रहे हैं जब कि गुजिस्ता दिनों काष्मिकचरला में एक केस हुआ जिसमें एक हरिजन बच्चे को मार दिया गया था। मैं खुद वहां हालात देख कर आया हूँ और उस बारे में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। यह बात सही है कि हरिजन बच्चे को मारा गया था। दूसरा जो कुछ लोगों का इस सदन में चार्ज था कि एक हरिजन औरत को नंगा करके धुमाया गया तो वह चार्ज बिलकुल गलत और झूठ है। मैंने खुद जाकर देखा है और इस बारे में तहकीकात की है। वह लड़के के मारे जाने की बात तो ठीक थी लेकिन वह औरत को नंगा करके धुमाने की बात गलत है। मेरा जिला भी है और यह मैं पूरी जांच पड़ताल करने के बाद कह रहा हूँ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है कि मंत्री महोदय ने जैसे अभी कहा कि जहां पर यह घटना घटी है वह उनका जिला है या उनकी कांस्टीट्यूएंसी है, इस बात के बिस्तार में न जाते हुए मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि यह घटना उस हरिजन बालक के साथ आंध्र प्रदेश में जो घटी वह कोई एक अकेली घटना नहीं है बल्कि उसके बाद भी कई उस प्रकार की घटनाएं घटी हैं जो कि आंध्र के समाचार पत्रों में और दूसरे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं लेकिन इतनी बातों के जैसे हरिजनों को इस तरीके से मारने या उनके साथ दुर्व्यवहार करने के अलावा क्या आपके कानों में इस तरह की भी घटनाएं सुनने में आई हैं जैसे कि आदिलाबाद का जो आदिवासी क्षेत्र है वहां उन आदिवासियों की निर्धनता का, गरीबी का लाभ उठाकर ईसाई पादरी वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, यदि हां, तो उसकी रोकथाम के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री मुख्याल राय : मैं यह चीज साफ़ कर दूँ कि जो हरिजन लड़के को मारा गया वह मेरी कांस्टीट्यूएंसी नहीं है। महबूबनगर के जिस

मात्रले का जिक्र हुआ है वह मेरी कांस्टीट्यूंसी है। चूंकि उन्होंने कहा मैं इसलिए कहता रहा हूं कि दोनों जगहों पर मैं जाकर असलियत के बारे में छानबीन करूंगा और जांच पड़ताल करने के बाद सदन को मैं उसके बारे में रिपोर्ट सबमिट करूंगा।

श्री रामगोपाल शालबाले : ईसाई मिशनरियों के बारे में पूछे गये सवाल का तो जवाब दे दीजिये।

SHRI P. ANTONY REDDY : I regret that the hon. Member is indulging in a generalisation based on a single, particular, individual case. Actually, the Andhra Pradesh Government is providing considerable facilities for the educational uplift and rehabilitation of Adivasis. Are Government aware that the Andhra Government is giving such facilities and is trying to do its best for the improvement of the lot of Harijans and Adivasis ?

SHRI MUTHIYAL RAO : I am thankful to the hon. Member for giving the information.

श्री शिवचरण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले 20 साल से हरिजनों और आदिवासियों की दशा सुधारने के झूठे आश्वासन दिये जाते रहे हैं :

“जवानी बात करने से सियासत कैसे बदलेगी

अमल से दूर हो रहना तो आदत कैसे बदलेगी ?”

ऐसी घटनाएं आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में भी हुई हैं। सिकन्दराबाद के अन्दर भी ऐसी घटना हुई है जहां कि 14 वर्ष के लड़के को जान से मार डाला गया तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? 20 साल तक हरिजनों और आदिवासियों की दशा सुधारने के झूठे और महज कागजी आश्वासन देते रहे लेकिन क्या दरअसल कोई भी अमल में आपने उसके लिए इंतजाम किया ?

MR. SPEAKER : This is about Andhra only; he cannot roam about the whole of India.

श्री चंद्रजीत यादव : क्या मंत्री महोदय यह बताना की कृपा करेंगे कि यद्यपि यह बात सही है कि पिछले 20 वर्षों में हरिजनों और आदिवासियों की दशा सुधारने के हेतु काफी प्रयास किया गया है, सरकार द्वारा दलित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्न किया गया है लेकिन बावजूद उन प्रयासों के आज वस्तु-स्थिति यह है और हांलाकि उनको संविधान में गारंटी दी गई है और सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए की गई नीति सम्बन्धी घोषणाओं के बावजूद भी, शीड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की उनके बारे में जो रिपोर्ट आती हैं उनसे खुद विदित है कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में यह जो दलित वर्ग है जिसके कि उत्थान के लिए सरकार प्रयास कर रही है, सरकार की नीतियों की घोषणाओं के बावजूद और उन सारी बातों के बावजूद भी आज यह वर्ग काफी पिछड़ा हुआ है। इसी का मतीबा यह होता है कि इस प्रकार की घटनायें आज भी हो रही हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए चूंकि भूमिहीनों को भूमि देने आदि का काम राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा भूमि उन लोगों को मिल नहीं पाती है क्योंकि भूमि देने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है और वे दूसरे लोगों को भूमि दे देते हैं—क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से परामर्श कर के चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान कोई विशेष योजना बनायेगी जिससे उन लोगों की आर्थिक परिस्थिति ठीक हो सके ?

श्री मृत्याल राव : हरिजनों की स्थिति बुरी है, मैं इसको मानने के लिये तैयार हूं, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी भूला नहीं जा सकता कि हरिजनों की स्थिति में आजादी के बाद काफी तरक्की हुई है। आज मुल्क में हजारों की तावाह में प्रोजेक्ट्स हैं, कितने ही लोगों को मौकरी मिली हैं, इस सदन में और हर असेम्बलियों में काफी हरिजन मेम्बर हैं,

मिनिस्टर हैं, काफी गैजेटेड आफिसर्स हैं । लेकिन मैं इस बात को भी मानने के लिये तैयार हूँ कि उनकी माली हालत उतनी नहीं सुधरी है जितनी हम चाहते हैं या गवर्नमेंट चाहती है । इसकी वजह यही है कि मुल्क की माली हालत खराब है । जिस दिन मुल्क की माली हालत अच्छी हो जायेगी, उस दिन हरिजनों की हालत अच्छी करने की पूरी पूरी कोशिश की जायेगी ।

**श्री चन्द्रजीत यादव :** मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने पूछा था कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या चौथी पंच-वर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से परामर्श करके कोई विशेष योजना बनायेगी जिससे केन्द्रीय सरकार जितना करना चाहती है, और वह हो नहीं रहा है, वह पूरा किया जा सके ?

**श्री मृत्याल राव :** मैंने कहा कि सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स से जरूर कहेगी । लेकिन बदकिस्मती यह है कि हर एक स्टेट में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं । इसलिए जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से काम नहीं हो पाता है ।

**श्री रबी राय :** हमको लगता है कि मंत्री महोदय ने इस सवाल की गम्भीरता को समझा नहीं है । आप जानते हैं कि हम लोगों ने इस सवाल को यहां उठाया । उसके बाद हम खुद हैदराबाद गये । "पेट्रियाट" में यह खबर छपी थी, और उस सिलसिले में हमारे खिलाफ और श्री कंबर लाल गुप्त के खिलाफ आंध्र प्रदेश की विधान सभा में स्वाधिकार भंग की नौबत तक आ गई थी । क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि कन्यकचला गांव में जो लड़का जलाया गया था, दो दिन हुए यह खबर छपी कि उसका मामला कोर्ट से खारिज हो गया ? क्या इससे यह पता नहीं चलता कि इस मामले में उच्च जाति के लोग अब हरिजनों पर अत्याचार करेंगे ? आज मंत्री महोदय होम मिनिस्ट्री से सम्बन्धित नहीं हैं, वह तो समाज

कल्याण विभाग के मंत्री हैं, लेकिन क्या उनको मालूम है कि आंध्र प्रदेश में, और खासकर आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के सीमा पर जो श्रीकाकुलम जिला आंध्र प्रदेश का है, वहां के आदिवासी बहुत गरीब हैं, उनमें बहुत असन्तोष है तथा वह हिंसात्मक आन्दोलन करने के लिये तैयार हैं ? क्या मंत्री महोदय, आंध्र प्रदेश जाकर आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से बात करके वहां के हरिजनों की भलाई के लिए कोई कदम उठायेंगे ?

**श्री मृत्याल राव :** जहां तक केस के खारिज होने का ताल्लुक है, उस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है । सरकार का फर्ज सरकार ने अदा किया . . . . .

**श्री रबी राय :** नहीं ।

**श्री मृत्याल राव :** सब कुछ किया । और कोर्ट का फर्ज कोर्ट ने अदा किया । इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ । बाकी रहा सवाल आदिवासियों का । तो हम और हमारे साथी हमेशा जाते हैं और उनसे मिलते भी हैं और जो कुछ कर सकते हैं वह करते भी हैं । आप अगर कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूँ । हम खूब कर रहे हैं ।

**श्री कांबले :** जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि इस देश की हालत अब तक ठीक नहीं हुई है, जब तक वह ठीक नहीं होती तब तक हरिजनों का काम ठीक से नहीं हो सकता । ऐसी हालत में हरिजनों की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिये गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है ?

**श्री मृत्याल राव :** मैंने कभी इस तरह से नहीं कहा । मैंने कहा कि देश की आर्थिक परिस्थिति खराब है ।

**एक भ्रान्तीय सदस्य :** क्या केवल हरिजनों के लिये खराब है ?

**श्री मृत्याल राव :** सबके लिये खराब है ।

**SHRI HEM BARUA :** Since the Reddis and the Khammas are supposed to be the most dominating community in Andhra Pradesh and it is under the dispensation of these communities that the Harijans and the Adivasis are suffering like anything, there is an invitation to Father Ferrer.....

**MR. SPEAKER :** That is the complaint of Mr. Sheo Narain also here.

**SHRI HEM BARUA :**....to come and among these people, which is the right thing to do. I should say that this is a sad commentary on the activities of the Government. In that context, may I know what special steps do the Government propose to take to bring the Harijans and Adivasis to the level of Reddis in Andhra Pradesh?

**SHRI S. M. BANERJEE :** I have heard the hon. Deputy Minister with rapt attention and he said that there was nothing wrong in Andhra Pradesh about the Harijans. After the Thimma Reddi episode, is it a fact that all the newspapers in Andhra, both the English and the Telugu newspapers, which highlighted the point how Thimma Reddy behaved or how the boy was burnt, were punished and declared by the Andhra Government as communal papers? I should like to know whether it is a fact that the accused who was responsible for the burning of the boy and the march of certain Harijan naked women....

**SHRI MUTHYAL RAO :** That is untrue; it is not a fact.

**SHRI S. M. BANERJEE :** I always listen to him patiently even if he says untrue things.

I want to know the circumstances leading to the acquittal of the person who was said to be responsible for marching these ladies naked. Has the Government appealed against that decision of the court?

**SHRI MUTHYAL RAO :** I cannot answer this because I have already said that the Government of Andhra Pradesh had taken the necessary steps and they had gone to the court and it is for the court to decide. I do not know whether the Government of Andhra Pradesh is going to appeal.

**SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH :** Will the hon. Minister be pleased to confess honestly before this House that the experience of the working of the last twenty years of the Harijan Welfare fund has proved that these

funds had been appropriated by the self-proclaimed Harijan leaders at all levels belonging to all parties and had not gone to the welfare of the Harijan communities with the result that there is tremendous dissatisfaction among the entire Harijan community on the administration of the Harijan social welfare schemes. In view of this do Government propose to make Harijan welfare a central subject?

**SHRI ASOKA MEHTA :** No, Sir. What we are trying to do is that the Scheduled Castes and Tribes should have their legitimate share in the general welfare programmes. In the Fourth Plan attempts are being made to earmark certain proportion from the general development programmes for the Scheduled Castes and Tribes, over and above the special funds allotted for them.

**SHRI E. K. NAYANAR :** [As disciples of Mahatma Gandhi, they are indulging in the kicking and burning of Harijans in Andhra...*(Interruptions.)* I want to know whether a number of police camps were instituted in the Srikakulam, Khammam and Nalgonda districts, hunting the tribal people, and appropriating their land, and whether the Government will take any serious steps to redress the grievances of the Harijans. May I also know, if the Minister is so impatient, whether the truth of the situation about the Harijans in Andhra Pradesh will come before parliament?

**SHRI MUTHYAL RAO :** As far as the Andhra Pradesh Government is concerned, we will request them to send us a report about the police camps. As far as the conditions of the Harijans are concerned, I have explained to him that we, the Central Government, are going to take care about it, and at the same time, there is a certain amount of money being misused; for example, his own Government in Kerala and some of the State Governments are misusing the amount.

**SHRI E. K. NAYANAR :** You come to Kerala.

**SHRI MUTHYAL RAO :** I know; they are misusing certain amounts.

**SEVERAL HON. MEMBERS :** rose—*(Interruption.)*

**MR. SPEAKER :** Order, order. Hon. Members will kindly sit down.

**SHRI E. K. NAYANAR :** It is an insinuation on Kerala.

**SHRI A. SREEDHARAN :** He should not make such a remark. Let him withdraw it. (*Interruption*)

**SEVERAL HON. MEMBERS :** rose—

**SHRI A. SREEDHARAN :** He must withdraw the statement.

**MR. SPEAKER :** All of you will kindly sit down.

**SHRI SHEO NARAIN :** Rose—

**MR. SPEAKER :** You should also sit down, Mr. Sheo Narain. Now, insinuations are wrong, whether they are thrown from that side to this side or from this side to that side of the House. I have been appealing to all hon. Members. (*Interruption*) Will you kindly sit down now? Insinuations are bad. Therefore, may I request the senior Cabinet Minister to say what the position is?

**SHRI ASOKA MEHTA :** There is no desire to cast aspersion on any State Government, I can assure you.

**SHRI RANGA :** What did he say?

**MR. SPEAKER :** It is wrong to cast aspersion against any State Government.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। उसका इस प्रश्न से सम्बन्ध है। मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए एक राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह हरिजनों के लिए दिये गये धन का दुरुपयोग कर रही है। क्या इस तरह के आरोप लगाने की इजाजत दी जा सकती है।

**MR. SPEAKER :** Order, order. Shri Tridib Kumar Chadhuri.

**SHRI H. N. MUKERJEE :** Sir, on the point raised by Shri Vajpayee..

**MR. SPEAKER :** That is what I said. The Deputy Minister said something, and the senior Minister said, no, there is no insinuation against any Government. It is wrong.

**AN HON. MEMBER :** Expunge it. (*Interruption*)

**MR. SPEAKER :** Therefore, there is no expunging it; it does not arise nor is it unparliamentary or something like that. It does not arise.

**SHRI VAJPAYEE :** The hon. Minister can withdraw the remark.

**MR. SPEAKER :** It has been corrected.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मंत्री महोदय के रिमार्क्स कार्रवाई में से निकाल दिये जायें।

**SHRI H. N. MUKERJEE :** Sir, excuse me..

**MR. SPEAKER :** The senior Minister has corrected it.

**SHRI H. N. MUKERJEE :** Here is a Deputy Minister who said very clearly and categorically that some State Governments are misusing the money, and just before that, he had made reference to a particular State Government. The senior Minister said later on that no insinuation was intended. This is a categorical assertion—no insinuation—and should it remain on record?

**MR. SPEAKER :** I have studied very clearly the powers of the Speaker about expunging from the record.

**AN HON. MEMBER :** Let him withdraw the remark.

**SHRI E. K. NAYANAR :** He must withdraw the remark. (*Interruption*)

**SHRI VISWANATHA MENON :** The Deputy Minister is a liar. (*Interruption*).

**MR. SPEAKER :** We have had enough of shouting. Shouting alone is not going to solve any problem. I asked the senior Minister whether he would correct it if there is no truth in it. It is a question of fact rather they can say, here is the money given for this purpose. Here is the money spent. They can collect the details and then place it on the Table without any insinuation.

**SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :** Are they prepared to do it?

**MR. SPEAKER :** Even now I would request the senior Cabinet Minister to look into it and see how much money was allotted and whether that money was spent for this purpose or for something else. These facts may be given to this House and then we can judge whether the insinuation was really correct or not. Sitting in the Chair, I cannot condemn anybody. On behalf of the whole House, I request the senior Cabinet Minister to collect the information and place it before the House.

**SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :** You should direct him, not request him.